DECEMBER 2011

The Hindu, Saturday, December 24, 2011

More Japanese Aid for Rajasthan Water Project

Jaipur: The Japanese financial assistance for the Nagaur Lift Water Supply Project has been revised to Rs.2,1999 crore from the earlier amount of Rs.1,774 crore. The proposal is for supply of surface water from the Indira Gandhi Cancal Project to Rajasthan's fluoride-affected district of Nagaur. The project, financed through the Japanese International Cooperation Agency (JICA), will cover 978 villages and seven towns.

According to a communication from Union Minister of State for Rural Development Jairam Ramesh to Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, the proposal has been revised following a suggestion from the JICA mission taking into account the latest schedules of rates and incorporating the fluorosis mitigation programme.

A six-member fact-finding team of JICA had visited Nagaur in the third week of October to dicuss the modalities of the project. The Japanese group was also promised government land for the prject,.

The revised estimates put the total cost of the project at Rs.2,938 crore, out of which Rs.339 crore will be contributed by the Union Government under the National Rural Drinking Water Programme. The State will have to put in a share of Rs.400 crore. The revised project does not have the urban component that was present in the original proposal.

The seven towns that will get drinking water from the project are Kuchaman, Nawan, Makrana, Parbatsar, Deedwana, Ladnun and Degana.

The ground water in Nagaur has high fluoride presence which causes fluorosis and other diseases of the bones and teeth in the local population. Availability of fresh drinking water is going to provide much-needed relief to the people here and bring down their medical expenses sharply.

The availability of water will also make a big difference to the economy of the mineral-rich Nagaur as paucity of water has been holding up its industries. The district has superior breeds of livestock but animal husbandry has remained a neglected area for want of water.

The physical works of the project will start in September 2013 and it is scheduled for commissioning in October 2016.

The Hindu, Thursday, December 29, 2011

National seminar on eco-friendly crop protection

In recent years, there has been renewed interest in popularizing organic and consumer-safe pest management technologies, o cater to organic and export-focus cultivation of crops in India.

Need for Promotion

A national seminar on Biotechnological approaches and eco-friendly crop protection towards promoting knowledge transfer and technology awareness was organized by the Sun Agro biotech Research Centre (SABRC) and the Department of Zoology, University of Madras in Chennai.

The event was inaugurated by Dr.P.Murugesa Boopathy, Vice Chancellor, Tamil Nadu, Agricultural University.

He exhorted the scientific community to keep constantly reminding themselves of the need to keep evolving strategies and fine-tuning agro-technologies, so as to be able to provide assured and adequate food to the growing population.

Need for support

He also emphasized need to adequately support the organic farming communities with appropriate technologies, especially eco-friendly pest control options to be available at farm level.

He further pointed put the potential for public-private R&D collaboration as a vital link in catering to consumer safe produce by promoting organic technology products like biopesticdes and pheromone trapping systems.

Dr.J.Kannaiyan, President, Sun Agro Biotech Research Centre (SABRC), in his introductory remarks informed the delegates that SABRC is a technocrats-founded consortium, devoted to supporting R&D in developing eco-friendly agro products, and has been recognized by Govt. of India – Department of Scientific & Industrial Research (DSIR) as an approved centre for scientific and industrial R&D.

Past Initiatives

He also recalled the past initiatives of SABRC in convening tow such national seminars earlier in the last five years, with focus on organic and eco-friendly pest management technologies.

Dr.E.I.Jonathan, Director, Centre for Plant Protection Studies (CPPS), TNAU in his inaugural lecture spoke on the recent success of biological control of papaya mealy bug in the state.

He explained that this successful campaign for mass production and field release of the imported bioagent was an outstanding success story in biological pest control at national level. About 60 experts from several ICAR institutes and other Universities participated.

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 8 दिसम्बर • 2011

फाइबर आप्टिक नेटवर्क से जुड़ेंगी देश की पंचायतें

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि 'नई दूरसंचार नीति-2011' में गांव-गांव तक बेहतर और सस्ती दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि देश के हर नागरिक को दूरसंचार क्रांति का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो सके।

सिंह ने बुधवार को यहां दूरसंचार विभाग और उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 'इंडिया टेलीकाम 2011' का उद्घाटन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2011 में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक सस्ती और अच्छी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल होगा।

मुझे विश्वास है कि इस नीति से तीव्र आर्थिक वृद्धि के हमारे लक्ष्य के हासिल होने में मदद मिलेगी। तीव्र आर्थिक वृद्धि का लाभ देश के हर नागरिक को मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार दो साल में हर ग्राम पंचायत को ब्राडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रही है और इसके लिए प्रारंभिक 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से राष्ट्रीय आप्टिक फाइबर नेटवर्क

इंडिया टेलीकाम रिपोर्ट जारी करते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।

बनाने की योजना है। सिंह ने कहा, 'हमारी सरकार का प्रयास है कि देश में हर गांव पंचायत ब्राडबैंड से जुड़ जाए। चूंकि गांव पंचायतों की जरूरत को देखते हुए ऊंचे बैंडविड्थ की जरूरत होगी, इसलिए वहां फाइबर आप्टिक नेटवर्क पहुंचाना जरूरी है।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अगले दो साल में यह काम पूरा करने के लिए हाल में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय आप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) योजना मंजूर की है। इसके प्रथमिक चरण की लागत 20,000 करोड आंकी गई है तथा इस नेटवर्क से सेवाओं को निजी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी इतनी ही राशि के निवेश की जरूरत होगी। इस योजना से गांवों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सेवाओं को हासिल करने में बहुत आसानी होने तथा इससे और कई लाभ मिलने की उम्मीद है।'

उन्होंने कहा कि ब्रांडबैंड का प्रसार आर्थिक वृद्धि में बड़ा सहायक है। इसका प्रसार 10 प्रतिशत बढ़ने से अर्थव्यवस्था में औसतन 1.3 प्रतिशत की वृद्धि होती है। सिंह ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से फैलता दूरसंचार बाजार है। यहां हर महीने 1.8 करोड़ ग्राहक जुड़ रहे हैं। 2000 में जहां 100 में दो व्यक्तियों के पास मोबाइल फोन था, वहां यह अनुपात अब अगस्त 2011 में बढ़कर 72.1 प्रतिशत हो गया है।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 25 नवंबर 2011

महिला कृषकों के भी बनें क्रेडिट कार्ड : स्वामीनाथन

- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसान संगोष्ठी
- किसानों के हित में कई बदलाव करने की जरूरत

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : देश में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि विशेषज्ञ व राज्यसभा सांसद डॉ. एमएस स्वामीनाथन ने कहा कि अभी किसानों के हित में कई बदलाव करने की जरूरी है। सबसे पहले कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि या किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा महिला कृषकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी होने चाहिए। इससे कृषि का विकास होगा। स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आयोजित अंतरराज्यीय किसान संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

संगोष्ठी में भारी संख्या में राजस्थान से किसान पहुंचे थे। स्वामीनाथन ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ पुरुष किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं। महिला कृषकों के नहीं, जबकि देश में बड़ी संख्या में महिलाएं भी खेती के काम में लगी हैं। यदि महिला किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है तो वे लाभान्वित होंगी ही, कृषि उपज भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसके लिए बिल पेश करेंगे।

उन्होंने कहा कि 120 करोड़ आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसान व वैज्ञानिकों की भूमिका अहम है। इसलिए खेती ऐसी हो, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एचएस गुप्ता ने कहा कि महंगाई के कारण खेती में लागत बढ़ गई है। इसके मद्देनजर ऐसे शोध किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सके। बायो खाद उन्हीं में से एक है। इसमें लागत भी कम आती है और इस्तेमाल से उपज अच्छी होती है। इस दौरान संस्थान के संयुक्त निदेशक के विजय राघवन, मीडिया प्रभारी जेपीएस डबास व सभी विभागों के अध्यक्ष मौजूद थे।